

आजादी के बाद उच्च शिक्षा की भूमिका



स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा आयोग

स्वतंत्रता के बाद भारतीय शिक्षा प्रणाली, जो पहले केवल अभिजात वर्ग के लिए थी, स्वतंत्रता के बाद समाज के एक बड़े हिस्से के लिए सुलभ की गई। सरकार ने शिक्षा की चुनौतियों का समाधान करने, व्यापक शिक्षा नीतियों की अनुशंसा करने और भारत में शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए विभिन्न शिक्षा समितियों का गठन किया है।



1. विश्वविद्यालय शिक्षा समिति (1948)/राधाकृष्णन समिति

स्वतंत्र भारत में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा के लिए पहली समिति 1948 की विश्वविद्यालय शिक्षा समिति, राधाकृष्णन थी। भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा की स्थिति पर रिपोर्ट करने और सुधार और विस्तार का प्रस्ताव करने के लिए नियुक्त किया गया।

समिति ने उन विश्वविद्यालयों की स्थापना का लक्ष्य भी रखा जो समग्र छात्र व्यक्तित्व के विकास के लिए ज्ञान और बुद्धिमत्ता प्रदान करते हैं। इस रिपोर्ट ने भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा प्रणाली के पुनर्निर्माण का सुझाव दिया।

2. मुदलियर आयोग (1952-1953)

भारत सरकार ने मद्रास विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉ ए. लक्ष्मणस्वामी मुदलियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा का गठन किया।

- भारत में अपने सभी पहलुओं में माध्यमिक शिक्षा की तात्कालीन स्थिति पर पूछताछ करने और रिपोर्ट करने के लिए;

- आयोग ने जून 1953 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- इसके उद्देश्य- संगठन, और माध्यमिक शिक्षा की सामग्री और प्राथमिक बुनियादी और उच्च शिक्षा से इसके संबंध के संदर्भ में इसके पुनर्गठन और सुधार के लिए उपाय सुझाना।
- सुझाव दिया गया है कि औद्योगिक शिक्षा उपकर नामक उपकर लगाया जाएगा, जो राशि एकत्र की जाएगी वह माध्यमिक स्तर पर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए उपयोग की जाएगी।
- अनुशंसा की जाती है कि किसी भी वर्ग में भर्ती होने वाले लड़कों की अनुकूलतम संख्या 30 होनी चाहिए और किसी भी मामले में अधिकतम 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए; पूरे विद्यालय में अनुकूलतम संख्या 500 होनी चाहिए जबकि अधिकतम 750 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- सुझाव दिया गया है कि 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की मांग करने वाले संविधान के अनुच्छेद 45 के तहत निर्देशक सिद्धांत की प्रारंभिक पूर्ति के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

3. भारतीय शिक्षा आयोग, (1964-66)/कोठारी आयोग

भारतीय शिक्षा आयोग (1964-1966), जिसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा भारत में शैक्षणिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करने, शिक्षा के सामान्य प्रतिमान को विकसित करने और भारत में शिक्षा के विकास के लिए नीतियों और दिशानिर्देशों की सलाह देने के लिए गठित एक तदर्थ आयोग था। इसका गठन 14 जुलाई 1964 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में किया गया था।

समिति की अनुशंसाएं इस प्रकार थीं:

- 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की मांग करने वाले संविधान के अनुच्छेद 45 के तहत निर्देशक सिद्धांत की प्रारंभिक पूर्ति के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।
- क्षेत्रीय भाषाओं को संभव समय पर संबंधित क्षेत्रों के लिए प्रशासनिक भाषा बनाया जाना चाहिए।
- अंग्रेजी भाषा शैक्षणिक कार्य और बौद्धिक अंतर-संचार के लिए उच्च शिक्षा में संपर्क-भाषा के रूप में सेवा करने के लिए। हिन्दी को गैर-हिन्दी क्षेत्रों में संपर्क-भाषा के रूप में और हिन्दी के प्रसार के लिए।

- त्रि भाषा सूत्र: संशोधित त्रि भाषा सूत्र में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए:
 - ✓ मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषाएँ;
 - ✓ संघ की आधिकारिक भाषा या संघ की सहयोगी आधिकारिक भाषा जब तक कि यह अस्तित्व में है संघ की आधिकारिक भाषा; तथा
 - ✓ एक आधुनिक भारतीय या विदेशी भाषा के तहत (a) और (b) में शामिल नहीं है और शिक्षा के माध्यम के रूप में इस्तेमाल हैं उनके अलावा।
- न केवल अशिक्षा के परिसमापन पर, बल्कि नागरिक और व्यावसायिक दक्षता और नागरिकों के सामान्य सांस्कृतिक स्तर को बढ़ाने के लिए वयस्क शिक्षा के कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।
- केंद्र और राज्य सरकारों को सभी संस्थानों में नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों में शिक्षा शुरू करने के उपाय अपनाने चाहिए।
- सामाजिक और राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रमों का स्कूलों और कॉलेजों में शैक्षिक अध्ययन के साथ समवर्ती गठन और उन्हें एन.एस.एस. जैसे सभी चरणों में सभी छात्रों के लिए अनिवार्य बनाना।
- आम स्कूल प्रणाली - स्कूल शिक्षा प्रणाली का एक अच्छा मानक बनाना: (10 + 2 + 3 प्रणाली)। नई शैक्षिक प्रणाली में सम्मिलित होने चाहिए-
 - a) पूर्व-स्कूल शिक्षा के 1 से 3 वर्ष
 - b) 4 से 5 वर्ष का निचला प्राथमिक चरण
 - c) 3 या 2 वर्ष का उच्च प्राथमिक चरण
 - d) 3 या 2 वर्ष का निचला माध्यमिक चरण
 - e) व्यावसायिक शिक्षा का 2 वर्षों का उच्चतर माध्यमिक चरण
- इसने सरकार को कॉलेज शिक्षा के व्यावसायिककरण पर अधिक जोर देने का सुझाव दिया।
- शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में सुधार किया जाना चाहिए, शिक्षक शिक्षा संस्थानों में सुधार और प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार।
- प्राथमिक स्तर पर पुस्तकों और लेखन सामग्री की मुफ्त आपूर्ति, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के सभी संस्थानों में पुस्तक बैंकों और पाठ्यपुस्तकों, पुस्तकालयों का प्रावधान।
- स्कूल पाठ्यक्रम के सुधार के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग, प्रशिक्षण महाविद्यालयों, राज्य शिक्षा संस्थानों और स्कूल शिक्षा के बोर्डों द्वारा अनुसंधान किये जाने चाहिए।

4. शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति (1968)

1968 में भारत सरकार ने कोठारी आयोग की अनुशंसा के जवाब में शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति तैयार की थी।

इसकी अनुशंसाएं थीं:

- भारतीय संविधान में प्रस्तावित 6-14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा।
- अनुशंसित क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यमिक विद्यालयों में उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- यह विचार था कि स्कूलों में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनना था और यह हिंदी को राष्ट्रभाषा मानता था।
- इसने संस्कृत का विकास भी प्रदान किया, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक थी।
- इसने भारत सरकार से अनुशंसा की कि राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर खर्च किया जाए।

5. शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति (1986)

इस समिति की अनुशंसाएं थीं:

- इसमें गरीबों के लिए अध्येतावृत्ति का प्रावधान था।
- इसमें प्रौढ़ शिक्षा प्रदान करने के लिए, उत्पीड़ित समूहों से शिक्षकों की भर्ती पर जोर दिया गया।
- यह दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना में सहायक था।
- इसने शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी के उद्भव के लिए भी मंच तैयार किया, इसके अतिरिक्त निजी उद्यम के लिए तकनीकी शिक्षा क्षेत्र को बड़े पैमाने पर खोलने के लिए।

6. शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति (1992)

भारत सरकार ने शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति के प्रावधान के प्रभाव का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए 1990 में आचार्य रामामूर्ति की अध्यक्षता में एक आयोग स्थापित किया था।

समिति की प्रमुख अनुशंसाएं इस प्रकार थीं:

- शिक्षा के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई थी।
- विकास को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत करने पर जोर दिया।
- छात्रों में नैतिक मूल्यों के विकास पर जोर दिया।

7. यशपाल समिति की रिपोर्ट

वर्ष 2009 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम.एच.आर.डी.) ने उच्च शिक्षा पर एक समिति का गठन किया था जिसे यशपाल समिति के नाम से जाना जाता था। समिति के अध्यक्ष यशपाल थे, जिन्हें भारत में उच्च शिक्षा के लिए सुधारों की जाँच करनी थी। यशपाल विश्व स्तर पर प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी, शैक्षिक और उच्च शिक्षा सुधारक प्रोफेसर थे।

अपनी रिपोर्ट में, यशपाल समिति ने एक विश्वविद्यालय के विचार पर जोर दिया और कई बड़े संरचनात्मक परिवर्तनों की वकालत की।

यशपाल समिति की रिपोर्ट की महत्वपूर्ण अनुशंसाएं निम्नलिखित हैं:

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम.एच.आर.डी.) को समिति द्वारा सौंपी गई अंतिम रिपोर्ट में, यह अनुशंसा की गई थी कि मानित विश्वविद्यालय की स्थिति को छोड़ दिया जाना चाहिए।
- यह भी अनुशंसा की गई थी कि सभी योग्य समझे जाने वाले मानित विश्वविद्यालयों को या तो पूर्ण-विकसित विश्वविद्यालयों में बदल दिया जाना चाहिए या उन्हें खत्म करना होगा।
- रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य के लिए जी.आर.ई. जैसे टेस्ट की आवश्यकता है।
- समिति ने अनुशंसा की कि एन.सी.टी.ई., ए.आई.सी.टी.ई., यू.जी.सी. और अन्य जैसे निकायों को उच्च शिक्षा और अनुसंधान आयोग (सी.एच.ई.आर.) - सात सदस्यीय निकाय द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।
- यह अनुशंसा की गई थी कि यह नया नियामक राजनीतिक दबावों से मुक्त होना चाहिए।
- सी.एच.ई.आर. के अध्यक्ष की स्थिति चुनाव आयुक्तों के समानांतर होने की अनुशंसा की गई थी।
- यह अनुशंसा की गई थी कि विश्वविद्यालयों को सभी शैक्षणिक जिम्मेदारियों को उठाना चाहिए, अन्य नियामकों जैसे कि भारतीय विधिज्ञ परिषद, भारतीय चिकित्सा परिषद आदि के अधिकार क्षेत्र को प्रशासनिक मामलों तक सीमित करना।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि आई.आई.टी. और आई.आई.एम. को पूर्ण विश्वविद्यालयों के रूप में काम करने के लिए विविधता लाने और विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019

- यह एस.आर. सुब्रमण्यन समिति की रिपोर्ट और के. कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर तैयार किया गया और एमएचआरडी द्वारा प्रस्तुत एक व्यापक दस्तावेज है।
- इसमें एक नया पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना प्रस्तावित की गई है, जिसमें 5 + 3 + 3 + 4 डिजाइन है, जो कि 3-18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को कवर करता है।
- इस नीति में एक नया राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण (SSRA) बनाने का प्रस्ताव है।
- यह 800 विश्वविद्यालयों और 40,000 कॉलेजों को लगभग 15,000 बड़े, बहु-विषयक संस्थानों में समेकित करना चाहता है।
- इस नीति में तीन प्रकार के उच्च शैक्षिक संस्थानों (HEI) को पेश करने का प्रस्ताव है: अनुसंधान विश्वविद्यालय, शिक्षण विश्वविद्यालय और स्वायत्त डिग्री देने वाले कॉलेज।
- संसद के एक अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) नामक एक स्वायत्त निकाय स्थापित करने का इसका प्रस्ताव है।
- एमएचआरडी का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय (एमओई) किया जाएगा।
- इसका उद्देश्य 2025 तक पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना और 2025 तक सभी के लिए मूलभूत साक्षरता / संख्यात्मकता प्रदान करना है।
- एक शीर्ष निकाय - राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या नेशनल एजुकेशन कमीशन का गठन किया जाना है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे।

Education Commissions in India Post Independence

Indian Education System After Independence, which was earlier exclusive to the elite, is made accessible to a large segment of society after independence. The Government has set up various education committees to address the challenges of education, recommend comprehensive education policies and improve the education system in India.



1. University Education Committee (1948) / Radhakrishnan Committee

The first committee for the most important education in independent India was the University Education Committee of 1948, Radhakrishnan. Appointed to report on the status of Indian university education and propose improvements and extensions.

The committee also aimed to establish universities that provide knowledge and wisdom for the development of the overall student personality. This report suggested rebuilding the education system in accordance with the Indian Constitution.

2. Mudaliar Commission (1952-1953)

The government of India appointed the secondary education commission, under the chairmanship of Dr. A. Lakshmanswami Mudaliar, then Vice- Chancellor of Madras University.

- To enquire into and report on the present position of Secondary education in India in all its aspects ;
- The commission submitted its report in June 1953.
- Suggest measures for its reorganization and improvement with particular reference to the aims, organization, and content of secondary education and its relationship to Primary Basic and Higher Education
- Suggested that A cess called the industrial education cess be levied, the amount collected to be utilized for the furtherance of technical and vocational education at the secondary stage.

- Recommended that the optimum number of boys to be admitted to any class should be 30 and the maximum should not in any case exceed 40; the optimum number in the whole school should be 500 while the maximum should not exceed 750.
- Suggested that efforts should be made for the early fulfillment of the Directive Principle under Article 45 of the Constitution seeking to provide free and compulsory education for all children up to the age of 14.

3. Indian Education Commission, (1964-66)/ Kothari Commission

Indian Education Commission (1964-1966), popularly known as Kothari Commission, was an ad hoc commission set up by the Government of India to examine all aspects of the educational sector in India, to evolve a general pattern of education and to advise guidelines and policies for the development of education in India. It was formed on 14 July 1964 under the chairmanship of Daulat Singh Kothari, then chairman of the University Grants Commission.

Recommendations of The Committee were as follows:

- Efforts should be made for the early fulfillment of the Directive Principle under Article 45 of the Constitution seeking to provide free and compulsory education for all children up to the age of 14.
- Regional languages to be made language of administration for the regions concerned at the earliest possible time.
- English language to serve as a link-language in higher education for academic work and intellectual inter-communication. Hindi to serve as the link language and spread of Hindi in non-Hindi areas;
- Three Languages Formula: The modified Three Language Formula should include the following:
 - ✓ The mother tongue or the regional languages;
 - ✓ The official language of the Union or the associate official language of the Union so long as it exist; and
 - ✓ A modern Indian or Foreign Language not covered under (a) and (b) and other than that used as the medium of instruction.
- Promotion of programmes of adult education aiming not only at liquidation of illiteracy, but also at raising the civic and vocational efficiency and general cultural level of the citizens;
- Centre and State Governments should adopt measures to introduce education in moral, social and spiritual values in all institutions
- Organization of social and national service programmes concurrently with academic studies in schools and colleges and to make them obligatory for all students at all stages like NSS.
- Common School System - maintaining a good standard of School educational system :(10+2+3 system). The new educational system should consist of

- (a) 1 to 3 years of pre-school education
 - (b) Lower primary stage of 4 to 5 years
 - (c) Higher primary stage of 3 or 2 years
 - (d) Lower secondary stage of 3 or 2 years
 - (e) Higher secondary stage of 2 years of vocational education
- It suggested government to give more emphasis on Vocationalisation of College education.
 - Teacher education programme should be improved, Improvement of teacher education institutions and expansion of training facilities
 - Free supply of books and writing materials at the primary stage, the provision of book banks and textbooks, libraries in all institutions of secondary and higher education,
 - For the improvement of school curricula research should be undertaken by University Departments of Education, Training Colleges, State Institutes of Education and Boards of School Education

4. National Policy on Education(1968)

In 1968 the Government of India had formulated the National Policy on Education in response to the recommendations of the Kothari Commission.

The Recommendations of it were:

- Compulsory education to children in the 6-14 years age group as proposed in The Indian Constitution
- Recommended Regional languages must be encouraged for being used in secondary schools.
- It was of the opinion that English had to be the medium of instruction in schools and it considered Hindi as the national language
- It also provided the development of Sanskrit, which was the symbol of India's cultural heritage.
- It recommended to The Government of India that 6% of the national income be spent on Education

5. National Policy on Education(1986)

The recommendations of this committee were:

- It had provision of fellowship for the poor
- It emphasized imparting adult education, recruitment of teachers from oppressed groups
- It was instrumental in setting up the Indira Gandhi National Open University at Delhi

- It also set the stage for the emergence of Information technology in education, besides opening up the technical education sector in a rather big way to private enterprise

6. National Policy on Education (1992)

The Government of India had set up a commission under the chairmanship of Acharya Ramamurti in 1990 to reassess the impact of the provision of National Policy On Education.

The major recommendation of the committee were as follows:

- Central advisory board of education was set up
- Stressed on promotion of development and strengthening national integration
- Stressed on developing moral values among students.

7. Yashpal Committee Report

In the year 2009, the Ministry of Human Resource Development (MHRD) had set up a Committee on Higher Education known as Yashpal Committee. The chairman of the committee was Yash Pal, for examining reforms to be brought about in higher education in India. Yashpal was a globally renowned physicist, academic, and higher education reformer Professor.

In its report, the Yashpal Committee laid emphasis on the idea of a university and advocated a number of major structural changes.

Following are the important recommendations of the Yashpal Committee Report:

- In the Final Report submitted by the committee to the Ministry of Human Resource Development (MHRD), it was recommended that the deemed university status should be abandoned.
- It was also recommended that all the deserving deemed universities should be either converted to full-fledged universities or would have to be scrapped.
- The report also said that a GRE like test needs to be evolved for the purpose of university education.
- The committee recommended that the bodies like the NCTE, AICTE, UGC and the other must be replaced by a Commission for Higher Education and Research (CHER) – a seven member body.
- It was recommended that this new regulator must be free from political pressures.
- The position of the chairperson of CHER was recommended to be parallel to that of the election commissioners.
- It was recommended that the universities must take up all the academic responsibilities, restricting the jurisdiction of the other regulators such as the Bar Council of India, the Medical Council of India etc to administrative matters alone.
- The report said that IITs and IIMs should be encouraged to diversify and expand their scope to work as full-fledged universities.

National Education Policy 2019

- It's a comprehensive document submitted by MHRD prepared based on the recommendation of S.R. Subramanian Committee report and K. Kasturirangan Committee report.
- It proposes a new Curricular and Pedagogical Structure, with 5+3+3+4 design covering the children in the age group 3-18 years.
- The Policy Proposes to create a new State School Regulatory Authority (SSRA).
- It wishes to consolidate 800 universities & 40,000 colleges into around 15,000 large, multidisciplinary institutions.
- The Policy proposes to introduce three types of Higher Educational Institutions (HEIs): Research Universities, Teaching Universities and Autonomous degree-granting colleges.
- It Proposes to set up an autonomous body called the National Research Foundation (NRF) through an Act of Parliament.
- MHRD to be renamed as the Ministry of Education (MoE).
- It aims to universalize the pre-primary education by 2025 and provide foundational literacy/numeracy for all by 2025.
- An Apex body - Rashtriya Shiksha Aayog or the National Education Commission to be constituted. It will be chaired by the Prime Minister.

A large, faint, light blue watermark of the gradeup logo is centered on the page. It consists of a graduation cap icon above the word "gradeup" in a large, lowercase, sans-serif font.